क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रेस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय
RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
4-0 ब्लोक, आगाम नवकार कॉम्पलेकक्ष, नीयर सचिन रेल्वे स्टेशन,सचिन, सूरत-394230
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 168, गुरुवार, 12 जुलाई, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

यूपी के पूर्व सीएम एनडी तिवारी की हालत नाजुक, मैक्स में भर्ती

नई दिल्ली। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी (92) की हालत गंभीर बनी हुई है। उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने दिल्ली स्थित मैक्स अस्पताल में जाकर एनडी तिवारी का हालचाल पूछा है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों व परिवार के सदस्यों से बात कर उनकी तबीयत की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि एनडी तिवारी की हालत बेहद गंभीर है, क्योंकि कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। उन्हें दवाइयों से अधिक अब दुआओं की जरूरत है। मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी से भी मिले। रावत ने कहा कि एनडी तिवारी उनके लिए गुरु के समान हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार से गुर्दे ने काम करना बंद कर दिया है। इसके अलावा पेट में भी संक्रमण है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद 20 सितंबर 2017 को एनडी तिवारी को भर्ती करवाया था।

फिर लगी पेट्रोल-डीजल में आग, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा

नई दिल्ली। पिछले दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी दिखी जा रही थी लेकिन एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दमों में आग लगानी शुरु हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार छठे दिन बढ़ने को लेकर बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 'जनता त्रस्त है,लेकिन सरकार मस्त'है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा,पेट्रोल-डीज़ल के दाम लगातार छठे दिन बढ़े। पेट्रोल एक रुपये और डीज़ल 77 पैसे महंगा हुआ। यह आम आदमी की जेब पर डाका डालने वाली मोदी सरकार के लिये आम बात हो गयी है। सुरजेवाला ने आगामी लोकसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा,अब कुछ ही महीनों की बात है। महँगाई की काली रात के बाद फिर नई शुरूआत होगी।

ताजमहल को लेकर केंद्र को न्यायालय की फटकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को ताजमहल के संरक्षण को लेकर उठाए गए कदमों को लेकर केंद्र तथा उसके प्राधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुगलकाल की इस ऐतिहासिक इमारत के संरक्षण को लेकर कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। शीर्ष अदालत ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर कि उत्तरप्रदेश सरकार ताज महल की सुरक्षा और उसके संरक्षण को लेकर दृष्टि पत्र लाने में विफल रही है। इसके साथ ही,केंद्र को न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस महत्वपूर्ण स्मारक के संरक्षण को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं और किस तरह की कार्रवाई की जरूरत है,इस बारे में वह विस्तृत जानकारी पेश करे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एमबी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि ताजमहल के संरक्षण के बारे में संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को बताया कि आईआईटी-कानपुर ताजमहल और उसके आसपास वायु प्रदूषण के स्तर का आकलन कर रहा है और चार महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। केंद्र ने यह भी बताया कि ताजमहल और उसके इर्दगिर्द प्रदूषण के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष समिति का भी गठन किया गया है जो इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक के संरक्षण के उपाय सुझाएगी। ।

अमरनाथ यात्रा के लिये 4,956 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना

जम्मू। 29 जून से शुरु हुई अमरनाथ यात्रा में अमरनाथ गुफा के लिये 4,956 श्रद्धालुओं का एक नया जत्था बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आधार शिविर से रवाना हो गया। अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं के 11 वें जत्थे में 1,454 महिलाएं और 97 साधु शामिल हैं। जो 161 वाहनों में यहां भगवती नगर से अनंतनाग में पहलगाम और गंदेरबल जिले में बालटाल आधार शिविरों के लिये तड़के रवाना हुए।

यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- ताजमहल की सुंदरता नहीं बचा सकते तो ध्वस्त कर दें

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार, यूपी सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ताजमहल की समुचित देखभाल कर पाने में असमर्थ होने को लेकर जमकर फटकार लगाई. अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि प्रशासन ताजमहल को ठीक से संरक्षित करे, या फिर उसे ध्वस्त कर दें, नहीं तो कोर्ट उसे बंद कर देगी।

सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के ताजमहल को संरक्षित करने के लिए विजन डाक्यूमेंट पेश करने में विफल रहने से नाराज है. जज मदन बी.लोकुर व न्यायमूर्ति दीपक प्रशासन की तरफ से ताजमहल के संरक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाने से खफा थे और उन्होंने कहा कि यह सरकार की सरासर लापरवाही है।

खंडपीठ ने कहा- ताजमहल को संरक्षित किया जाना चाहिए

खंडपीठ ने कहा, ÷ताजमहल को संरक्षित करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है. ताजमहल को संरक्षित किया जाना चाहिए. या तो हम इसे बंद कर देंगे या आप इसे ध्वस्त कर दें या इसे संरक्षित करें।

अदालत ने कहा- ताजमहल एफिल टॉवर से ज्यादा सुंदर है

अदालत ने कहा कि ताजमहल एफिल टॉवर से ज्यादा सुंदर है और यह देश की विदेशी मुद्रा की समस्या को हल कर सकता है। अदालत ने कहा, एफिल टॉवर को आठ करोड़ लोग देखने जाते हैं, जो कि टीवी के एक टॉवर जैसा दिखता है। हमारा ताजमहल बहुत ज्यादा खूबसूरत है. यदि आप इसकी देखभाल करेंगे तो इससे आपकी विदेशी मुद्रा की समस्या हल होगी।खंडपीठ ने कहा, क्या आपको इस बात का अहसास है कि आपकी लापरवाही से देश को कितना नुकसान हुआ है? ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले खंडपीठ से कहा था कि वह अदालत के समक्ष ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षा के लिए एक विजन दस्तावेज पेश करेगी. ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था।अदालत ने कहा कि वह मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को दैनिक आधार पर करेगी. खंडपीठ ने केंद्र से उठाए गए कदमों का पूरा विवरण प्रस्तुत करने को कहा और ताजमहल की सुरक्षा के इरादे से कार्रवाई करने को कहा।

अदालत ने ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) के चेयरमैन को जोन में औद्योगिक इकाइयों के विस्तार को रोकने के आदेश के उल्लंघन को लेकर स्पष्टीकरण देने के लिए व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति होने का आदेश दिया। टीटीजेड 10,400 वर्ग किमी का इलाका है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा और राजस्थान के भरतपुर तक फैला हुआ है.उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि वह ताजमहल के चारों तरफ पर्यावरण की देखभाल की कोशिश कर रही है, जिससे ऐतिहासिक इमारत 400 सालों तक बनी रहे।

अटार्नी जनरल वेणुगोपाल ने सुको की सुनवाई से खुद को किया अलग

नई दिल्ली।अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने मंगलवार को समलैंगिकता के मुद्दे से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई में पेश होने से खुद को अलग कर लिया। अटार्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने संबंधित विधि अधिकारी को इस बारे में जानकारी दी है जो प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ के सामने इस मामले को संभाल रहे हैं। गौरतलब है कि समलैंगिकता अपराध है या नहीं, इसे तय करने के लिए कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वेणुगोपाल ने कहा कि उन्हें यह भी नहीं पता कि इस मुद्दे पर सरकार का क्या रुख है। वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि चूंकि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को फिर से अपराध की श्रेणी में लाने के 2013 के फैसले के खिलाफ दायर उपचारात्मक याचिका के संबंध में अदालत में पेश हुये थे।

सरकारी नौकरियों में एससी /एसटी के लिए आरक्षण पर अंतरिम आदेश से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली।

उच्चतम न्यायालय ने देश में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर 2006 के अपने पूर्व के आदेश के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने से बुधवार को इनकार किया। यह मामला क्रीमी लेयर लागू करने से जुड़ा हुआ था। बुधवार को इस मामले में प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर एवं न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि 2006 के फैसले-एम नागराज पर विचार के लिए सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ की जरूरत है। केन्द्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ को इस मामले की तत्काल सुनवाई करनी चाहिए क्योंकि विभिन्न न्यायिक फैसलों से उपजे भ्रम के कारण रेलवे और सेवाओं में लाखों नौकरियां अटकी हुई हैं। इसपर पीठ ने कहा कि एक संविधान पीठ के पास पहले ही बहुत सारे मामले हैं और इस मामले को अगस्त के पहले सप्ताह में ही देखा जा सकता है।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष 15 नवंबर को शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ केवल यह देखेगी कि क्या 2006 के एम नागराज तथा अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत है अथवा नहीं।

फीस न जमा करने पर स्कूल प्रबंधन ने 59 छात्राओं को 5 घंटे तक बनाया बंधक

नई दिल्ली।

देश में निजी स्कूलों की मनमानी से सभी लोग वाकिफ हैं, उनकी फीस को लेकर अभिभावकों से अक्सर विवाद होता रहता है। राजधानी दिल्ली के बल्लीमारान स्थित राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल में कथित तौर पर फीस जमा नहीं करने की वजह से बच्चियों को घंटों बेसमेंट में बंधक बनाकर रखा गया। पैरेंट्स इस बात से हैरान हैं कि महज फीस न चुकाने पर तहखाने (बेसमेंट) में बंधक बनाकर 59 बच्चियां 5 घंटे तक कैद रखी गईं। 40 डिग्री तापमान में भूखी-प्यासी बच्चियां दोपहर होने का इंतजार कर रही थीं, ताकि जल्दी से उनके माता पिता आकर ले जाएं। जब पैरेंट्स पहुंचे, देखते ही बच्चे बुरी तरह रो पड़े। परिजनों का आरोप है कि बेसमेंट में रूम के बाहर की कुंडी लगाई हुई थी। जब बच्चियों को लेने स्कूल पहुंचे तो स्टाफ भी संतुष्टि भरा जवाब नहीं दे सका। बच्चियों का गर्मियों में भूख-

प्यास से बुरा हाल था। अपने बच्चों की हालत देखकर परिजन भी बिफर गए। स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने जूवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

मामले ने मंगलवार को उस वक्त तूल पकड़ा जब इस हैरतअंगेज घटना का विडियो और तस्वीरें भी सामने आई। इसमें दिख रहा है कि छात्राओं को बेसमेंट में बंद किया गया है। ये विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। विडियो सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अभिभावकों में गहरा रोष है। विडियो में देखा जा सकता है कि लड़कियां बेसमेंट में फर्श पर बैठी हैं। आरोप था कि वहां पंखा भी नहीं थे। पैरेंट्स का दावा है कि उन्होंने जब तहखाने के दरवाजे खोले तो बच्चियां जमीन पर बैठी हुई थीं। अपने परिजनों को देखकर बच्चियों ने रोना शुरू कर दिया। बच्चियों को बेसमेंट में बैठाने के पीछे स्कूल का तर्क था कि उनकी जून महीने की फीस अब तक जमा नहीं की गई है, जबकि अभिभावकों ने स्कूल के आरोपों को खारिज करते हुए फीस समय पर जमा कराने की रसीदें भी पुलिस को दिखाई हैं। 40 डिग्री तापमान में 5 घंटों से भूखी प्यासी थीं और जब इसको लेकर बच्चियों के मां-बाप ने हेड मिस्ट्रेस फरहा डीबा खान से बात की तो उन्होंने बेहद ही बदतमीजी से बात की और स्कूल से बाहर निकाल देने की धमकी दी।

मोदी के एक राष्ट्र, एक चुनाव के प्रस्ताव को कांग्रेस किया खारिज

नई दिल्ली। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राष्ट्र, एक चुनाव के प्रस्ताव को संवैधानिक ढांचे के विरुद्ध करार दिया है। साथ ही आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपने इस 'जुमले' से लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर उसने विधि आयोग का रुख नहीं किया क्योंकि उसका रुख सर्वविदित है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव में कोई दम नहीं है। यह सिर्फ जुमला है। इसका मकसद लोगों को बरगलाना और मूर्ख बनाना है। सिंघवी ने कहा कि एक साथ चुनाव की बात सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन क्या यह संवैधानिक ढांचे को बरकरार रखते हुए व्यवहारिक रूप से संभव है। सिंघवी ने दावा किया कि इस विचार के पीछे इरादा अच्छा नहीं है। यह प्रस्ताव लोकतंत्र की बुनियाद पर कुठाराघात हैं। यह जनता की इच्छा के विरुद्ध है। इसके पीछे अधिनायकवादी रवैया है। उन्होंने सवाल किया।

फूड कमिश्नर ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरु करने से पहले कानून विभाग से मांगी सलाह

➪ अफसर के इस रवैये पर उखड़े केजरीवाल, भाजपा पर साधा निशाना

नई दिल्ली।

राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की अपनी महत्वाकांक्षी योजना में विलंब होता देख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खफा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा उनके कामों में अड़ंगा डाल रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकारों की लड़ाई जीतने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप-राज्यपाल की आपत्तियों को खारिज करते हुए फूड एंड सप्लाई विभाग को राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने के आदेश दिए थे। लेकिन फूड कमिश्नर ने इस योजना पर विचार के लिए दिल्ली सरकार के कानून विभाग को भेजते हुए उससे सलाह मांगी है कि इस योजना के लिए क्या केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत है। खबरों के मुताबिक फूड कमिश्नर राशन

की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केंद्र सरकार द्वारा राइट टू फूड एक्ट के तहत कानून विभाग से मंजूरी चाहते हैं। फूड कमिश्नर द्वारा कानून विभाग को फाइल भेजे जाने से भड़के अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला और कहा कभी सुना था कि कोई अफसर सरेआम कैबिनेट और मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करने से मना कर दे? इसलिए भाजपा सेवा विभाग को अपने पास रखना चाहती है।

केजरीवाल ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि गरीबों के लिए लागू की जाने वाली इस योजना में भाजपा अड़ंगा लगा रही है। केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी दिल्ली देख ले कि किस बेशर्मी से भाजपा दिल्ली के गरीबों की %घर-घर राशन% स्कीम रोक रही है। अगली बार वोट देने जाओ तो यह याद रखना। केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के साथ केजरीवाल की लड़ाई सेवा विभाग को लेकर है और केजरीवाल का आरोप है कि इसी अधिकारों का इस्तेमाल कर उपराज्यपाल सीधे-सीधे अफसरों को काम करने से रोक रहे हैं। केजरीवाल सरकार का मानना है कि फूड सिक्योरिटी कानून के तहत गरीबों को मुफ्त राशन देना केंद्रीय कानून है, लेकिन उनको राशन कैसे मुहैया कराया जाए या उसकी वितरण पद्धति क्या हो यह फूड सिक्योरिटी एक्ट का हिस्सा नहीं है बल्कि राशन के वितरण का अधिकार और उसकी व्यवस्था करने का अधिकार राज्यों के पास है।

बुराड़ी केस में एक और दावा, बीड़ी वाले बाबा से मिलता था भाटिया परिवार

नई दिल्ली।

दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक घर से एक ही परिवार के निकले 11 शव ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को भी सन्न करके रख दिया था। पड़ताल में हर रोज नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं और अब तक हुई पड़ताल में कई बातें अब तक निकलकर सामने आयी है। लेकिन, एक अज्ञात शख्स ने पुलिस को जो चिट्ठी लिखी है वह और भी चौंकाने वाला है।

पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी में उस अज्ञात शख्स ने दावा किया कि भाटिया परिवार और किसी तांत्रिक के बीच संपर्क था और परिवार लगातार उस बाबा से सलाह मशविरा कर रहा था।

पुलिस को बुराड़ी में 11 लोगों की मौत के मामले में अभी तक अपनी जांच में किसी बाहरी व्यक्ति या किसी तांत्रिक का हाथ होने का सबूत तो नहीं मिला है। लेकिन इस अज्ञात शख्स चिट्ठी ने फिर से बुराड़ी सुसाइड में नया मोड़ ला दिया है।

पुलिस कमिश्नर को यह बिना नाम की चिट्ठी 3 जुलाई को लिखी गई है। चिट्ठी लिखने वाले शख्स का कहना है कि बुराड़ी में जिस परिवार के 11 लोगों ने धार्मिक अंधविश्वास में फंसकर मोक्ष पाने की कामना से सामूहिक आत्महत्या की, वह दिल्ली के ही किसी बाबा के संपर्क में था। अनाम लिखी गई इस चिट्ठी में उस शख्स ने किसी बीड़ी वाले बाबा का जिक्र है। चिट्ठी लिखने वाले का दावा है कि बुराड़ी के भाटिया परिवार का इस तांत्रिक के पास आना जाना था।

चिट्ठी में बताया कि दिल्ली के कराला में रहने वाले इस तांत्रिक का असली नाम चंद्रप्रकाश पाठक है। दिल्ली के कराला इलाके में बीड़ी वाले और दाढ़ी वाले बाबा के नाम से मशहूर है यह तांत्रिक चंद्रप्रकाश पाठक। चिट्ठी के मुताबिक, बीड़ी वाले बाबा अपने आप को हनुमान का भक्त कहता है और शाम 6 बजे तक झाड़ फूंक करता है। इतना ही नहीं, इस बाबा की पत्नी भी तांत्रिक है।

बनने से पहले ही एचआरडी से जियो इंस्टीट्यूट को मिला उत्कृष्ट का दर्जा, आलोचना शुरू

नई दिल्ली

जियो इंस्टीट्यूट ऑफ रिलायंस फाउंडेशन को उत्कृष्ट संस्थानों की लिस्ट में डालने पर केंद्र सरकार के फैसले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का ट्वीट रिट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार अंबानी की जेब में है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया है। ''पहले कांग्रेस सरकार अंबानी की जेब में थी, अब मोदी सरकार की, कुछ बदला क्या? यशवंत सिन्हा ने एक ट्वीट में कहा था, जियो इंस्टीट्यू की अभी स्थापना नहीं हुई है। उसका अस्तित्व नहीं है। फिर भी सरकार ने उसे एमिनेंट टैग दे दिया। ये मुकेश अंबानी होने का महत्व है। दरअसल, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) की तरफ से 6 इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान (इंस्टीट्यूट

ऑफ एमिनेंस) का दर्जा दिया है। इन 6 इंस्टीट्यूट में जियो इंस्टीट्यूट ऑफ रिलायंस फाउंडेशन को भी शामिल किया है। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि जियो इंस्टीट्यूट अब तक बना ही नहीं तो सरकार कैसे उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दे सकती है? इसे लेकर लोग सोशल मीडिया पर जियो इंस्टीट्यूट को ट्रोल कर रहे हैं। गौरतलब है कि एचआरडी मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बंबई और आईआईएससी बेंगलोर, मनिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, बिट्स पिलानी और जियो इंस्टीट्यूट को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा देने की घोषणा की है।तमाम विवादों के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पूरे विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि यूजीसी रेगुलेशन 2017, के क्लॉज 6.1 के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल नए संस्थानों को भी शामिल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य निजी संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के एजुकेशन इंफास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बढ़ावा देना है, ताकि देश को इसका लाभ मिल सके।

चिदंबरम का आरोप, एयरसेल-मैक्सिस मामले में पीछे पड़ी हुई है ईडी

नई दिल्ली।

पिछले कुछ दिनों से अदालत के चक्कर कट रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर आरोप लगाया कि वह एयरसेल-मैक्सिस मामले में उनके पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है और आरोपों का जवाब अदालत में दिया जाएगा। पूर्व वित्तमंत्री की यह टिप्पणी उस वक्त आई है जब दिल्ली की एक अदालत ने चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 7 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया। बुधवार को कांग्रेस नेता चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा,एयरसेल-मैक्सिस मामले में किसी अपराध का उल्लेख करते हुए प्राथमिकी नहीं है। ईडी पीछे पड़ी हुई है और आरोपों का जवाब अदालत में दिया जाएगा। चिदंबरम ने 30 मई को अदालत से इस मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण देने का अनुरोध किया था। उनका कहना था

कि इस मामले के सभी साक्ष्यों की प्रकृति दस्तावेजी लगती है और वे पहले से मौजूदा सरकार के पास हैं। इसके अलावा,उनसे कुछ और बरामद नहीं किया जाना है। अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले से जुड़े एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा क्रमश-2011 और 2012 में दर्ज दो मामलों में कार्ति को आजतक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। यह मामला एयरसेल में निवेश के लिए मैसर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेस लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने से जुड़ा है।

राजनीति

पंजाब में मोदी ने किसानों से कहा-

कांग्रेस ने बनाया वोट बैंक, हमने दी ऐतिहासिक एमएसपी : प्रधानमंत्री मोदी

चंडीगढ़ ।

पंजाब के मुक्तसर में कृषि कल्याण रैली से पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 70 सालों में किसानों ने जिस पार्टी पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया उस पार्टी ने इस भरोसे का सम्मान नहीं किया. उन्होंने हमलों को और तीखा करते हुए कहा कि किसानों से सिर्फ वादे किए गए और उस पार्टी ने सिर्फ एक परिवार की भलाई के लिए काम किया.

अपनी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जब से इस सरकार ने एमएसपी बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला किया तब से किसानों को राहत मिली है और उनकी एक बड़ी चिंता समाप्त हो गई है. अब किसनों को अपने उत्पाद पर ज़्यादा भरोसा है.

कांग्रेस पर किसानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाने के अलावा पीएम मोदी ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की और कहा कि इससे प्रदूषण फैलता है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पराली जलाने की समस्या पर केन्द्र गंभीरतापूर्वक काम कर रहा है.

रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसान की फसल बर्बाद से बचाने के लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चला रही है. इसी तरह देश भर में नए गोदाम बनाए जा रहे हैं, फूड पार्क बनाए जा रहे हैं. उनका कहना था कि सरकार पूरी सप्लाई चेन को सुधार में लगी है और कोशिश है कि फसल की बर्बादी रुके.

अपनी सरकार की यूरिया नीति का बखान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक जमाना था जब यूरिया के लिए किसानों को लाठियां खानी पड़ती थी, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है. आज किसानों को 100त्र नीम कोटिंग यूरिया पर्याप्त मात्र में उपलब्ध है।

पंजाब के मुकसर में कृषि कल्याण रैली से पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 70 सालों में किसानों ने जिस पार्टी पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया उस पार्टी ने इस भरोसे का सम्मान नहीं किया. उन्होंने हमलों को और तीखा करते हुए कहा कि किसानों से सिर्फ वादे किए गए और उस पार्टी ने सिर्फ एक परिवार की भलाई के लिए काम किया. अपनी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जब से इस सरकार ने एमएसपी बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला किया तब से किसानों को राहत मिली है और उनकी एक बड़ी चिंता समाप्त हो गई है. अब किसनों को अपने उत्पाद पर ज्यादा भरोसा है।

रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसान की फसल बर्बाद से बचाने के लिए सरकार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चला रही है. इसी तरह देश भर में नए गोदाम बनाए जा रहे हैं, फूड पार्क बनाए जा रहे हैं. उनका कहना था कि सरकार पूरी सप्लाई चेन को सुधार में लगी है और कोशिश है कि फसल की बर्बादी रुके.

संपादकीय

सस्ती थाली

दिल्ली के गरीब लोगों के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है कि अब उन्हें दस रुपये में भोजन की थाली आसानी से उपलब्ध होगी। उत्तर दिल्ली नगर निगम ने इसके लिए अपने क्षेत्र में 500 ऐसे केंद्र खोलने का फैसला किया है, जहां यह थाली उपलब्ध होगी। यह परियोजना दक्षिण दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में भी शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि जल्द ही दिल्ली के अन्य नगर निगमों में भी इसे विस्तार दिया जाएगा। ऐसी योजानाएं जब भी शुरू होती हैं, उन्हें चुनाव से जोड़कर देखा जाने लगता है। 2019 का आम चुनाव बहुत दूर नहीं है, इसलिए ऐसा सोचा जाना स्वाभाविक भी है। हालांकि यह कोई नई योजना नहीं है। काफी पहले जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं, तो उन्होंने एक जन आहार योजना शुरू की थी, ताजा योजना को उसी का एक विस्तार कहा जा सकता है। ये जरूर है कि इसे अब दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत लागू किया जा रहा है, जिसे पिछले साल 25 दिसंबर को यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर शुरू किया गया था। दिल्ली के लिए इस तरह की योजना जरूरी भी है, यहां गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाला गरीब तबका तो है ही, काम और मजदूरी की आस में यहां लगातार ऐसे लोग आते हैं, जो घर-परिवार से दूर होते हैं, उनके पास खाना बनाने की व्यवस्था नहीं होती, और न ही इतना पैसा होता है कि बाजार के किसी रेस्तरां में पेट भर सकें। वैसे दिल्ली में हम जो प्रयोग देख रहे हैं, वह देश के कई हिस्सों में पहले ही बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु में 2013 में ही हो गई थी। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता द्वारा शुरू की गई अम्मा उनावगम यानी अम्मा कैंटीन नाम की यह योजना गरीबों को पांच रुपये में सांभर और चावल उपलब्ध कराने के लिए काफी चर्चा में रही थी। तमिलनाडु की इसी योजना से प्रभावित होकर पड़ोस के राज्य आंध्र प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना लागू की गई थी। ओडिशा की आहार योजना भी इसी से मिलती-जुलती थी, जिसकी सफलता का कई जगह जिक्र होता है। ऐसी ही एक योजना उत्तराखंड में भी शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी योजना शीघ्र शुरू किए जाने की खबर है। ऐसी योजनाएं एक तो गरीबों को सस्ता और अच्छा विकल्प दे सकती हैं और दूसरे, काम की तलाश में इधर-उधर आने-जाने वाली फ्लोटिंग पॉपुलेशन का बड़ा सहारा बन सकती हैं। बस शर्त यही है कि परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता से किसी सूरत में कोई समझौता न हो और योजना सरकारी भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। दक्षिण के राज्यों में इसकी कोशिश भी हुई है और अब उत्तर के राज्यों की परीक्षा है। वैसे अपने देश में बहुत सी धार्मिक और दानदाता संस्थाएं इस तरह के आयोजन करती रही हैं, हालांकि उनकी क्षमता और पहुंच इतनी नहीं है कि वे आबादी के बड़े हिस्से का पेट भर सकें। लेकिन एक दूसरी तरह से देखें, तो किसी भी समाज में इस तरह की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। गरीबों का सस्ता भोजन या जरूरत पड़े तो मुफ्त भोजन मिले, ऐसी खाद्य सुरक्षा का इंतजाम तो सरकारों को करना ही होगा। मगर इसे तात्कालिक उपाय भर ही माना जाना चाहिए। अंत में तो हमें अर्थव्यवस्था को उस बिंदु तक ले जाना होगा, जहां हर कोई अपने भोजन का इंतजाम खुद कर सके। इस मंजिल की ओर हमें तुरंत बढ़ना चाहिए।.

एक साथ चुनाव

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रयोगधर्मी राजनेता हैं। उनका महती राजनीतिक सपना है कि देश में लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथहों। चुनाव सुधार की दृष्टि से यह प्रगतिशील विचार है। अगर इस प्रस्ताव के पक्ष में आम राय बन जाती है, तो चुनाव खर्च पर संतोषजनक पाबंदी लग सकती है। देश में साल भर कहीं न कहीं कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं, जाहिर है कि इस मद में बड़े पैमाने पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री के इस प्रस्ताव के पक्ष में राजनीतिक दलों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। गैर-एनडीए दलों में समाजवादी पार्टी, अन्ना द्रमुक, तेलंगाना राष्ट्र समिति और बीजद ने प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, तेलुगू देशम, माकपा, भाकपा आप, जनता दल (एस) और फॉर्वड ब्लॉक ने विरोध जताया है। कांग्रेस अभी अपना पत्ता खोली नहीं है और भाजपा सभी दलों के विचार जानने के बाद ही विचार प्रकट करेगी। हालांकि भाजपा इस प्रस्ताव का समर्थन ही करेगी। विरोधकरने वाले राजनीतिक दल इस प्रस्ताव को अलोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था की प्रकृति के प्रतिकूल ठहरा रहे हैं। वास्तव में इनके तकरे से सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि ऐसा लगता है कि इन राजनीतिक दलों को देश के राजनीतिक इतिहास की जानकारी नहीं है। 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर 1967 तक लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। इसलिए कि उन दिनों देश में एक पार्टी यानी कांग्रेस का प्रभुत्व था। लेकिन जनाकांक्षाओं को पूरा करने में जब कांग्रेस असफल होने लगी तब क्षेत्रीय पार्टियों का विकास हुआ और राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल प्रभावित होने लगे। इसलिए यह यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रस्ताव से संविधान की बुनियादी संरचना बदल जाएगी। सच तो यह है कि यह व्यवस्था लागू होने से राष्ट्रीय दल मजबूत हो सकते हैं, और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कम हो जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि देश में द्विदलीय पण्राली का विकास हो सकता है, जो लोकतंत्र और राष्ट्रीय हित, दोनों के लिए सकारात्मक है। इसलिए क्षेत्रीय दलों को अपने छोटे-छोटे राजनीतिक स्वार्थो को तिलांजलि देकर राष्ट्र हित में सोचना चाहिए। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकासित देशों में लोकतंत्र की सफलता का एक कारण यह भी है कि वहां द्विदलीय व्यवस्था है।

चौं रे चम्पू/अशोक चक्रधर

मंचीय नहीं, लोक कवि

चौं रे चम्पू! हरिद्वार में गंगा स्नान कियौ कै नायं?-काग स्नान किया, छींटे मार लिए। बरसात के कारण जल में मिट्टी का अस्तित्व अलग से दिख रहा था। मिट्टी बैठती तो अपन भी बैठ जाते, लेकिन कवि सम्मेलन का तीसरा अधिवेशन जो गंगा जी के घाट पर जयराम आश्रम में चल रहा था, वहां मंच के कवियों की काफी मिट्टी बैठ गई। मिलने बतियाने से उनका मन निर्मल हुआ।-तफसील ते बता!-उद्घाटन सत्र में डॉ. वेद प्रताप वैदिक ने देशभर से आए सौ के लगभग मंचीय कवियों से कहा कि आप लोग लोक कवि हैं, लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी! स्वायत्त और सम्प्रभु! किसी के नौकर नहीं हैं आप। आपको जो सुनने आते हैं, कोरे कागद की तरह आते हैं। वे लोग अगर किसी नेता को सुनने जाएंगे तो कोरे कागद की तरह नहीं जाएंगे। वहां तो उनके दल के विचारों की इबारत पहले से लिखी होगी। फिर चचा, उन्होंने कहा कि लोक कवि की बात भदलोक, अभदलोक, अतिभदलोक के सारे लोग समझते हैं। आप लोक कवि हैं, इसीलिए सर्वलोक के कवि हैं। कवि खुश हो गए सारे। -खुस चौं न होते भला?-मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि ये लोक कवि भद्र, अभद्र, अतिभद्र सबकी भद्दरा उतार देते हैं। भद्दरा उतारना आप तो समझ गए चचा, पर ब्रजमंडल के बाहर की तो छोड़ो, मैं भी कल ही समझा कि भद्दरा का संबंध भद्रता से रहा होगा। भद्दरा उतारने का मतलब है, सामने वाले की भद्रता, अभ्रद्रता, अतिभद्रता का नकली आवरण उतार देना। लोक कवि की कविता सीधा और कभी-कभार सांकेतिक प्रहार करती है। हार को जीत और जीत को हार करती है। लोक कवि की कविता बड़ी कविता है या नहीं, इस बात पर स्वनामधन्य समीक्षकों ने कोई विषेश कृपा-निगाह नहीं डाली। इसकी वैसे भी कोई खास आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो पहले से ही समझ में आ रही है, उसकी समीक्षक और क्या व्याख्या करें! और क्यों करें! -और कौन-कौन आए?-अखबारों में पढ़ ही चुके होंगे! अब तो कवियों के फेसबुक, ट्विटर, वॉट्सएप देखिए! यू-टयूब देखिए। कविगण हाईटैक हो चुके हैं।

जलवायु संकट का एक पहलू है आबादी

अनिल पी जोशी पर्यावरणविद्

कहा जाता है कि मानव आबादी वर्ष 1350 में ब्लैक डैथ (प्लेग) के बाद लगातार बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि 1350 के बाद शुरू हुई और उसका कारण था बेहतर स्वास्थ्य व अधिक खाद्य उत्पादन। इसकी वृद्धि दर वर्ष 1980 के बाद घटी पर पूर्णांक संख्या फिर भी बढ़ी ही है। एक हालिया शोध ने ये बताया है कि पांच जुलाई 2018 को 763.4 करोड़ लोग धरती पर है। यह भी माना जाता है कि पृथ्वी चार अरब लोग बेहतर जीवन जी सकते हैं और यह धरती 16 अरब से ज्यादा आबादी का भार नहीं ढो सकती, यानी यह उसकी अंतिम सीमा है। यह भी माना जा रहा है कि जनसंख्या वर्ष 2040-50 तक आठ से 10.5 अरब तक पहुंच जायेगी। क्योंकि प्रति वर्ष 7.4 करोड़ लोग धरती पर बढ़ते जा रहे है। दुनिया में 7 देश ऐसे हैं जिनके कारण वर्ष 2050 तक आधी आबादी का कारवां होगा।

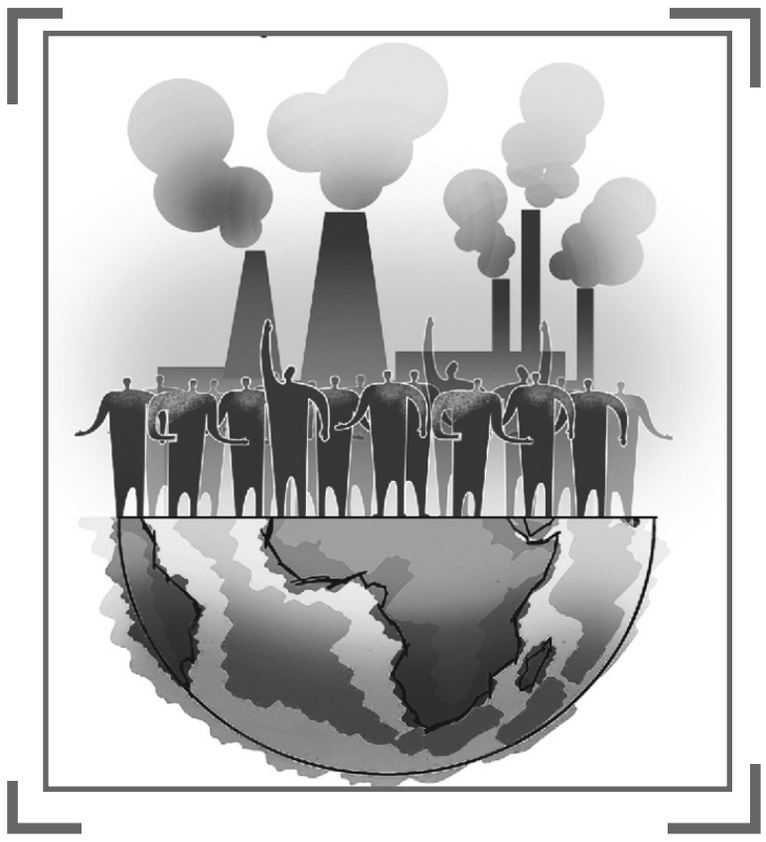

हमारी धरती पर कितनी आबादी होनी चाहिए यह चर्चा बहुत पुरानी है। प्राचीन लेखक तेर्तुल्लियन ने दूसरी सदी में ये कहा था कि आबादी पृथ्वी की क्षमताओं के अनुसार ही होनी चाहिये। यह भी बड़ी अजीब सी बात है कि 750 साल पहले मतलब उद्योग क्रांति से भी पहले दुनिया की संख्या बहुत धीमी गति से बढ़ती थी परंतु 19वीं सदी में आते आते यह संख्या अरबों में पहुंच गई। 18वीं सदी की इसी उद्योग क्रांति के बाद जनसंख्या वृद्धि भी हुई और साथ में प्राकृतिक संसाधनों का शोषण भी हुआ। इस सदी के अंत में जहां जनसंख्या अरब थी वो 20वीं सदी में आते आते 1.6 अरब हो गई और 20वीं सदी के अंत तक छह अरब पर पहुंच गई। वैसे थॉमस मॉल्थस जैसे विद्वान ने कभी यह भविष्यवाणी की थी कि मानव जाति संसाधनों की तुलना में कई गुना बढ़ जायेगी।

> बढ़ती आबादी के लिए संसाधन जुटाने की कोशिश में ही हम प्रकृति का ज्यादा से ज्यादा दोहन कर रहे हैं।

यह पृथ्वी कितनी आबादी का भारत ढो सकती है यह बहस भले ही सदियों से चल रही हो लेकिन 1994 से इसके विश्लेषण भी शुरू हो गए। तब इंटर ऐकेडमिक पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इसके कारण पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण जैसे मुद्दे खड़े होंगे। यूनाईटेड नेशन पॉपूलेशन असेंसमेंट की वर्ष 2004 की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। पर 2014 में साइंस मैगजीन ने इसका खंडन करते हुए बताया कि यह जनसंख्या वृद्धि अगली सदी तक चलेगी। वर्ष 2017 में ही 50 नोबेल पुरुस्कार विजेताओं ने सामूहिक रूप से एक पेटीशन में कहा कि अधिकतम मानव जनसंख्या और पर्यावरणीय क्षति दुनिया के दो बड़े खतरे बन चुके हैं। और इसी वर्ष 184 देशों के 15364 वैज्ञानिको ने माना कि बढ़ती जनसंख्या ही बिगड़ती सामाजिक,आर्थिक व पारिस्थितिकीय का कारण है।

पर आबादी कभी बहस का बड़ा मुददा नहीं बन पाती, क्योंकि इससे कईं चीजें जुड़ी हुई है। जनसंख्या के आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक पहलू जब भी चर्चा में आते है तो कई तरह के विवादों में अटक जाते हैं। हम जनंसख्या पर चर्चा से कतई नहीं कतरा सकते क्योंकि स्थिति लगातार विस्फोटक होती जा रही है। खासतौर से जब दुनिया के हर तीसरें व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं हासिल होता है। आधी आबादी के सर पर अपनी छत नहीं है, स्वास्थय सेवाएं मात्र 30-40 प्रतिशत लोगों तक ही पहुंचती हैं। इसी के चलते गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ा है।

इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर एक हैक्टेयर खेती 22 टन ही धान पैदा कर सकती है और उससे 1000 लोगों का ही पेटभर सकता है तो आगे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके साथ ही हमें बाकी प्राणियों के बारे में भी सोचना होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 1.4 लाख प्रजातियां धरती से विलुप्त होने की कगार पर है। जिनमें से 801 वन्यजीव भी शामिल है। वर्ल्डवाइड फंड फॉर नेचर की एक रिपोर्ट के अनुसार- आबादी अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो हमें डेढ गुना बड़ी पृथ्वी की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी तरफ बढ़ती जनसंख्या के कारण साफ पेयजल की उपलब्धता पर सीधा असर पड़ा है। बढ़ता वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिटटी व ध्वनि प्रदूषण सीधा बढ़ती जनसंख्या के कारण है। वर्ष 1970 से लेकर वर्ष 2015 के बीच में उर्जा के उपभोग में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मतलब 1970 में अगर उर्जा के उपयोग को शून्य मान लें तो 2010 में ये 150 गुना बढी वा 2025 तक आते-आतें ये 250 गुना हो जाएगी और इसके लिये हद से ज्यादा प्रकृति का शोषण होगा। हम जानते हैं कि दुनिया में बाल व शिशु मृत्यु दर बढ़ती गरीबी के कारण है। भुखमरी, कुपोषण व नई नई बीमारियों को सीधे-सीधे बढ़ती जनसंख्या से जोड़ा जा सकता है। दिक्कत यह है कि दुनिया में कुपोषित और अल्पपोषित लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हालत यहां तक पहुंच गई है कि ब्रिटेन जैसे सक्षम देश को अपनी आबादी के लिये खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ता है। लेकिन हर देश के लोग इतने खुशकिस्मत नहीं हैं, जिन देशों की आर्थिक स्थिति इतीन अच्छी नहीं हैं कि वे बड़ी मात्रा में आयात कर सकें वहां लोग कुपोषण और अल्पलोषण के शिकार हैं। अगर जनसंख्या की यह ही गति रही तो यह तो तय है कि अन्न से लेकर पानी और प्राणवायु तक सब पर बड़ा संकट आएगा। आज भी इन सभी संसाधनों पर पड़ने वाला दबाव साफ देखा जा सकता है। यह सब पिछले दो दशकों में ज्यादा गहरा हुआ है तो कल्पना की जा सकती है कि अगले 2-3 दशकों में परिस्थितियां कहां पहुंच जाएंगी। हमें बढ़ती जनसंख्या पृथ्वी की क्षमताओं और वर्तमान परिस्थितियों पर बड़ी और निर्णायक चर्चा अब करनी ही होगी। वर्ना यह दुनिया पहले संसाधनों के संकट और फिर उनके लिए युद्ध की ओर बढ़ेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

लिव इन रिलेशन

सहजीवन में गुजारे भत्ते का हक

अनूप भटनागर

'लिव इन रिलेशन' में रहने वाले वयस्क जोड़ों के मामले में प्रीवी काउंसिल से लेकर उच्चतम न्यायालय तक ने यह व्यवस्था दी है कि यदि कोई जोड़ा लंबे समय तक एक साथ रहता है और समाज उसे पति-पत्नी के रूप में मान्यता देता है तो इसे विवाहित जोड़ा माना जायेगा। अक्सर खबरें सुनने को मिलती हैं कि चार-पांच साल बगैर विवाह एक साथ रहने के बाद पुरुष पर उसकी महिला साथी ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। कुछ साल तक स्वेच्छा से एक साथ रहने के बाद इस तरह के आरोप के औचित्य पर बहस की जा सकती है। हाल ही में, उच्चतम न्यायालय के सामने एक बेहद रोचक मामला आया, जिसमें सहजीवन बिताने वाली महिला ने अपने पुरुष साथी से गुजारे भत्ते की मांग की। उसका दावा है कि उसके पुरुष साथी ने उससे शादी का वायदा किया था लेकिन बाद में वह मुकर गया। अब न्यायालय को यह फैसला करना है कि क्या सहजीवन बिताने वाले पुरुष को अपनी महिला साथी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया जा सकता है?

ऐसा करने से पहले न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की पीठ ने अटार्नी जनरल से अनुरोध किया है कि वह इस मामले में मदद के लिये अतिरिक्त सालिसिटर जनरल को नियुक्त करें। न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से भी इसमें सहयोग करने का आग्रह किया है। हालांकि, लिव इन रिलेशन के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने अनेक पहलुओं पर व्यवस्था दी है। ऐसा करते समय न्यायालय ने इसके लिये कुछ शर्तों पर खरा उतरना भी जरूरी किया है। इसमें पहली शर्त ऐसे जोड़े को समाज द्वारा एक-दूसरे का जीवन साथी स्वीकार करना, दूसरी, कानूनी दृष्टि से दोनों की उम्र विवाह करने वाली हो, तीसरी शर्त यह कि वे बिन ब्याहे जीवन गुजारने के बावजूद कानूनी तरीके से वैवाहिक जीवन व्यतीत करने की पात्रता रखते हों और चौथी शर्त यह कि वे स्वेच्छा से लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में रह रहे हों।

लिव इन रिलेशन का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कि बिन ब्याहे ही पति-पत्नी के रूप में लंबी अवधि तक एक साथ रहना और समाज में पति-पत्नी के रूप में ही खुद को पेश करना। न्यायालय की व्यवस्थाओं के अनुसार इस पैमाने पर खरा उतरने वाले जोड़ों से जन्म लेने वाली संतानों को न सिर्फ ऐसे व्यक्ति की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा बल्कि महिला को अपने जीवन साथी का निधन होने की स्थिति में उसकी भविष्य निधि और पेंशन सहित दूसरे कानूनी अधिकार भी मिल सकेंगे।

सहजीवन का मुद्दा, विशेषकर 2005 में महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून लागू होने के बाद से लगातार चर्चा में है। घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून के संदर्भ में न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति पिनाकी चन्द्र घोष की पीठ ने नवंबर, 2013 में अपने फैसले में कुछ दिशा निर्देश प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट किया था कि सिर्फ यौन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये सहजीवन का मार्ग अपनाने वाला वैवाहिक जीवन के तहत मिलने वाले लाभ पाने का पात्र नहीं हो जाता। दूसरे शब्दों में किसी पुरुष के साथ बिन ब्याहे जीवन गुजारने वाली महिला यदि गुजारा भत्ता और दूसरे अधिकार चाहती है तो उसे कुछ बुनियादी जरूरतें पूरी करनी होंगी।

घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून के तहत राहत प्राप्त करने से जुड़े मसले पर न्यायालय की व्यवस्था है कि यदि कोई महिला यह जानते हुए कि उसका साथी पुरुष पहले से ही विवाहित है, उसके साथ सहजीवन अपनाती है तो उसे इस कानून के तहत कोई राहत नहीं मिल सकती। इससे पहले, अक्तूबर, 2010 में तत्कालीन न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू और न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की पीठ ने एक फैसले में कहा था कि सहजीवन गुजारने वाले सारे मामले वैवाहिक स्वरूप के नहीं होते और ऐसे मामलों में महिला को गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता। इस पीठ ने तो यहां तक कहा था कि सिर्फ सप्ताहांत या एक रात साथ में रहना 'घरेलू रिश्ता' नहीं बनायेगा।

सहजीवन और बिन ब्याहे लंबे समय से जीवन व्यतीत कर रहे जोड़ों और इनसे जन्म लेने वाली संतानों के अधिकारों के संबंध में पहली बार 1927 में प्रीवी काउंसिल ने सुविचारित व्यवस्था दी थी। इसी व्यवस्था के आलोक में ही उच्चतम न्यायालय ने 1952 में गोकल चंद बनाम परवीन कुमार और फिर 1978 में बदरी प्रसाद के मामले में पति-पत्नी के रूप में सालों एक साथ गुजारने के तथ्य को महत्व दिया और माना कि कानूनी दृष्टि से ये विवाह था। दूसरी ओर, बंबई उच्च न्यायालय ने इस साल अप्रैल में ही एक फैसले में कहा है कि लंबे समय तक सहजीवन व्यतीत करने वाली महिला अपने पुरुष साथी से गुजारा भत्ता प्राप्त करने की हकदार है।

अब सवाल न्यायालय के विचारार्थ है कि क्या शादी का वायदा करके लंबे समय तक सहजीवन गुजारने वाला व्यक्ति यदि शादी से मुकर जाये तो क्या वह जीवन साथी को गुजारा भत्ता देने के लिये बाध्य है।

दिल्ली विवि

अंक आधारित प्रवेश परीक्षा क्यों?

डॉ. नवल किशोर

स्कूली जीवन के अंतिम वर्ष में बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ भविष्य में शिक्षा की संभावित दिशा भी उनके लिए चिंता का विषय होती है। स्नातक पाठय़क्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ संस्थाओं पर उनकी नजर होती है। दिल्ली विविद्यालय का एक केंद्रीय विविद्यालय होने के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी में स्थित होने के कारण अभ्यर्थियों के लिए स्वाभाविक मंजिल बन जाता है। यही कारण है कि प्रति वर्ष जून-जुलाई के महीने में दिल्ली विविद्यालय स्नातक पाठय़क्रमों में नामांकन की इच्छा रखने वाले छात्र-छात्राओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। कला, विज्ञान और वाणिज्य में स्नातक डिग्री के लिए 56000 सीटें निर्धारित हैं, जो दिल्ली विविद्यालय के करीब 70 कॉलेजों में बंटी हुई हैं। प्रत्येक कॉलेज अपने-अपने निर्धारित कट-ऑफ की सूचना दिल्ली विविद्यालय प्रशासन को देता है, और फिर दिल्ली विविद्यालय इन सूचनाओं को संकलित करके एक ऐसे कट-ऑफ की घोषणा करता है, जिसमें प्रत्येक कॉलेज की सूचना समाहित होती है। दिल्ली विवि में यह प्रवेश प्रक्रिया काफी वर्षो से चली आ रही है, और आम तौर पर इसमें कोई समस्या भी देखने में नहीं आई है। लेकिन हाल के वर्षो में विभिन्न बोडरे द्वारा घोषित परिणामों मे काफी असमानता देखी गई है, जिसके कारण कुछ राज्यों के छात्र-छात्राएं अपने बोर्ड में अच्छे अंक पाने के बावजूद दिल्ली विविद्यालय में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं, और दिल्ली विविद्यालय में नामांकन का अवसर पाना उनके लिए सपना बन कर रह गया है। इस तय को मानने के कारण मौजूद हैं कि दिल्ली विविद्यालय की स्वीकृत कट-ऑफ पण्राली विभिन्न बोडरे के बीच जो असमानता है, उसके बीच सामंजस्य स्थापित नहीं करती है, और एक बेहद असमावेशी प्रवेश पण्राली को जन्म देती है। देश के विभिन्न बोर्ड जैसे सीबीएसई, आईएससी तथा राज्यों के बोडरे के पाठय़क्रमों, मॉडरेशन और मूल्यांकन की प्रक्रिया को देखें तो ये बेहद असमान दिखते हैं। इसलिए यह सवाल राज्य बोडरे से निकले उम्मीदवारों के लिए काफी अहम है, जिनके टॉपर्स भी डीयू के कालेजों में प्रवेश पाने से वंचित रह जाते हैं। एक सूचना के अनुसार इस वर्ष के प्रतिभागियों का बोर्ड-केंद्रित अध्ययन करें तो चौंकाने वाले तय दिखेंगे। इस वर्ष दिल्ली विविद्यालय में स्नातक नामांकन के लिए कुल 278,574 ऑनलाइन आवेदकों में से 249,694 (90 फीसदी) अभ्यर्थी सीबीएसई बोर्ड से थे, जबकि बाकी अभ्यर्थियों में से 22,266 यूपी बोर्ड,10,858 हरियाणा, 3,856 आईएससी बोर्ड और 9681 अभ्यर्थी एनआईओएस बोर्ड से संबंधित थे। स्पष्ट तौर पर यह दिखता है कि देश के अधिकतर राज्य-बोडरे के छात्र उम्मीदवारी स्तर पर ही नदारद हैं, प्रवेश तो बहुत दूर की बात है। हम कह सकते हैं कि ये आवेदक संविधान द्वारा अवसर के अधिकार से ही वंचित रह जाते हैं। जाहिर है कि दिल्ली विविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया समावेशी नहीं दिखती। दो कारणों से ऐसा प्रतीत होता है। पहला, अंक-आधारित की के बजाय प्रवेश प्ररीक्षा को माध्यम के तौर पर क्यों नहीं अपनाया जा रहा, जबकि देश की अनेक शीर्ष संस्थाएं इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरा, अंक आधारित प्रवेश अगर बाध्यता है, तो अनेक बोडरे के बीच कोई तर्क संगत समानता की रेखा खींचने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है? तकनीकी और वैज्ञानिक युग में परंपरागत तरीके से अन्यायपूर्ण दिखने वाली इस प्रवेश पण्राली को ढोने का क्या औचित्य है? लगभग चालीस फीसदी युवा जनसंख्या के साथ भारत एक युवा देश है, और इसमें से बहुसंख्यक युवा गांव और कस्बों से अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं। इनमें से अधिकत्तर वंचित और उपेक्षित वर्ग से संबंध रखते हैं। संस्थाएं अगर इन युवाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होंगी तो राष्ट्र निर्माण अधूरा ही रह जाएगा। दिल्ली विविद्यालय देश का सबसे बड़ा विविद्यालय होने के नाते सबसे बड़ी संख्या में नामांकन का अवसर प्रदान करता है। अंक आधारित प्रवेश पण्राली राज्य बोडरे से निकले छात्र-छात्राओं की नजर में न्यायपूर्ण नहीं दिख रहा है। यह मानने का कारण मौजूद है कि बड़ी संख्या में मेधावी छात्र-छात्राएं बेहतर अवसर को पाने से वंचित रह जाते हैं। अगर मेधा विकास का मानक है, तो राज्य बोडरे के मेधावी छात्रों के लिए डीयू में अंक आधारित प्रवेश प्रक्रिया घातक है। ''दिल्ली दूर है' लोकोक्ति इस संदर्भ में सही चरितार्थ होती है।

संक्षिप्त

शॉर्ट सर्किट से घड़ी दुकान में लगी आग

बेतिया, जिले में बुधवार को मीणा बाजार स्थित एक घड़ी दुकान में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना टाउन थाना क्षेत्र के शोआ बाबू चौक की है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई। आसपास के कई दुकान भी आग की चपेट में आ गए। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दुकान मालिक अजय कुमार ने बताया कि अचानक जलने की बदबू आई और धुआं उठने लगा। वे तुरंत दुकान से बाहर आए और घटना की जानकारी लोगों को दी। इसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन करके घटना की जानकारी दी।

खेत में करानी पड़ी हेलिकाप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग

औरंगाबाद, जिले में एक हेलिकाप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलिकाप्टर को गोह प्रखंड के सहरसा गांव के खेत में उतारा गया। उड़ान के दौरान कुछ तकनीकी खामी आ गई थी, जिसके चलते हेलिकाप्टर को उतारना पड़ा। इसमें सीआरपीएफ के एडीजी, आईजी समेत 9 अधिकारी सवार थे। नक्सल प्रभावित जिला होने के चलते औरंगाबाद में आईईडी ब्लास्ट या फिर नक्सल हमले का डर रहता है। इसके चलते अधिकारी रिमोट एरिया में जाने के लिए हेलिकाप्टर का इस्तेमाल करते हैं। बुधवार सुबह 9 अधिकारी हेलिकाप्टर से भलुआही कैम्प जा रहे थे इसी दौरान उसे सहरसा गांव में उतारना पड़ा। हेलिकाप्टर हवा में चक्कर काटते हुए नीचे आने लगा तो गांव के लोग डर गए। हेलिकाप्टर जब खेत में उतरा तो ग्रामीणों की भी भीड़ जमा हो गई।

मशरूम से बदलेगी किसानों की किस्मत

सहरसा, मशरूम की खेती से इलाके के किसानों की किस्मत बदलने वाली है। अगवानपुर कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा सत्तरकटैया प्रखंड के दो गांव में इसकी खेती शुरू कराई गई है, लेकिन अब धीरे-धीरे दूसरे गांव के किसान भी इस खेती से जुड़ने लगे हैं। प्रखंड के बसिया घाट और नयानगर संथाली टोला में बड़े पैमाने पर हो रही मशरूम की खेती के बाद इसका विस्तार कोसी के सभी जिलों में कराने की योजना है। इस खेती में कम लागत में अधिक मुनाफा मिलने के कारण किसानों को काफी लाभ हो रहा है।

डबल डेकर पुल के शिलान्यास को लेकर खुशी हो रही है- तेजस्वी

पटना, बिहार के छपरा जिले में देश का सबसे लंबा फ्लाईओवर का निर्माण होगा। इसका आज सीएम नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया। इस पर खुशी जाहिर करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि डबल डेकर पुल के शिलान्यास को लेकर खुशी हो रही है। ट्वीट कर तेजस्वी यादव ने कहा 'मैंने इस पुल का सपना पथ निर्माण मंत्री रहते हुए देखा था' इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से की थी बात आज उसका शिलान्यास हो रहा है। मुझे खुशी हो रही है। तेजस्वी ने ट्वीट में लिखा कि मुझे खुशी है मेरे पिता की कर्मभूमि छपरा में जिस डबल

डेकर फ़्लाईओवर का सपना हमने पथ निर्माण मंत्री रहते देखा था एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से मिलकर उनके विशेष सहयोग व सीआरपीएफ के मद से देश के पहले डबल डेकर पुल की रूपरेखा तैयार की थी आज उसका शिलान्यास होने जा रहा है। वहीं तेजस्वी ने अपने अगले ट्वीट में एनडीए पर निशाना साधते हुए लिखा कि 18 वर्षों के अज़ीज साथी गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार अंदरखाने में मिलकर ऊपर से बनावटी विरोध प्रकट करते है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब दोनों के साथ वर्षों से अर्जित अति विशेष नॉलेज शेयरिंग एवं ट्रेनिंग देने अमित शाह बिहार आए थे। कुछ दिनों बाद बिहार में साइड इफ़ेक्ट्स दिखेंगे।

घर के बाहर सो रहे अधेड़ का अपहरण

भोजपुर, पीरो थाना क्षेत्र के मोथी गांव में घर के बाहर सो रहे सत्येंद्र सिंह नामक 50 वर्षीय व्यक्ति का अपहरण करने का मामला सामने आया है। इस मामले में अपहृत के पुत्र सौरभ कुमार सिंह के बयान पर पीरो थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोथी निवासी सत्येंद्र सिंह मंगलवार की रात अपने घर के बगल में स्थित गोशाला के पास चारपाई पर सोए हुए थे।

पंचायत सचिव का वेतन कटा

मधेपुरा, बैठक से गायब रहे चार पंचायत सचिव का वेतन काटा गया है। बीडीओ की इस कार्रवाई से प्रखंड कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया है। मालूम हो कि प्रत्येक माह मंगलवार को होने वाली बैठक में साप्ताहिक कार्यों की समीक्षा की जाती है। साथ ही अगले सप्ताह में किए जाने वाली कार्य योजना के संबंध में दिशा-निर्देश दिया जाता है।

मुखिया पद पर रामदयाल राय हुए विजयी

समस्तीपुर, जिले के वारिसनगर में पंचायत उपचुनाव के बाद हुए मतगणना में मुखिया पद के उम्मीदवार पूर्व मुखिया रामदयाल राय की जीत हुई। इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आफताब आलम को 559 मतों से पराजित किया। मतगणना के बाद निर्वाचीत पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाते हुए 10 दिनों में पंचायत को ओडीएफ कराने की बात कही। उप चुनाव के मतगणना में मुखिया पद के उम्मीदवार रामदयाल राय को 1322 मत, आफताब आलम को 763 मत, राजीव कुमार को 744 मत, विनोद शंकर राय को 503 मत, राजन कुमार को 107 मत, रामचन्द्र महतो को 45 मत तथा अर्जुन ठाकुर को 36 मत प्राप्त हुए।

फ्रीज किए जाएं मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खाते-एडीजी

रांची, झारखंड के एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) आरके मल्लिक ने चाइल्ड ट्राफिकिंग मामले पर राज्य सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ उन्होंने मिशिनरी ऑफ चैरिटी और इसके पांच एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन्स के सभी खातों को भी सीज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच में हमें चैरिटी द्वारा 121 बच्चों के बेचे जाने का रिकॉर्ड मिला है। पुलिस महानिदेशक डीके पांडेय ने भी मंगलवार को गृह सचिव एसकेजी रहाटे को पत्र लिखकर मिशनरीज ऑफ चैरिटी एंव उससे जुड़ी अन्य संस्थाओं के फंड की सूक्ष्म जांच केंद्र सरकार से कराने को कहा है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि केंद्र से अनुरोध किया जाए कि जांच पूरी होने तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी सहित सभी संस्थाओं के सभी बैंक एकाउंट फ्रीज कर दिए जाएं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के राजधानी के ईस्ट जेल रोड स्थित शेल्टर होम निर्मल हृदय की कर्मचारी और एक सिस्टर द्वारा अवैध रूप से बच्चों को बेचने का मामला सामने आने के बाद अब राज्य भर में संस्थान के क्रियाकलापों और फंडिंग की जांच तेज हो गई है। पुलिस महानिदेशक ने गृह सचिव को लिखे पत्र में कहा है कि इस मामले का खुलासा होने के बाद अनुसंधान एवं स्त्रोतो से मिली जानकारी और प्रमाण के अनुसार यह बात सामने आई है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी प्राप्त राशि का उपयोग इसके मूल उद्देश्य में न होकर अन्य कार्यों में कर रही है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के साथ पांच अन्य संस्थाएं जुड़ी हुई है। जिन्हें वर्ष 2006-07 से लेकर 2016-17 तक 11 वर्षों के दौरान 927.27 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है। मिशनी कोलकाता को वर्ष 2011-12 से लेकर 2016-17 तक 1.94 कररोड़ रुपए का विदेशी फंड मिला। वहीं मिशनरीज ऑफ चैरिटी फादर्स इंडिया को वर्ष 2011-12 से 2016-17 के बीच 27.71 करोड़ रुपए विदेशी फंड मिले। मिशनरी सिस्टर्स ऑफ मैरी हेल्प ऑफ चैरिटीयंस वेलफेयर सोसाइटी को वर्ष 2016-17 में 27.71 लाख रुपए का विदेशी फंड मिला है। गृह सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि द फारेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 की धारा 13 में एफसीआरए सर्टिफिकेट को निलंबित करने का प्रावधान है। धारा 14 में कैसिलेशन का अधिकार भी केंद्र सरकार को ही प्राप्त है। वहीं प्रत्येक राज्य की जांच एजेंसी की अपराध शाखा तभी जांच करने में सक्षम है जब राशि एक करोड़ से कम हो। एक करोड़ रुपए से अधिक राशि की जांच करने की सक्षम एजेंसी सीबीआई है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के विभिन्न जिलों में 12 बाल गृह चल रहे हैं। जिसमें एमसी सुरुचिकला गोड्डा, एमसी साटिनो रोड डालटनगंज, एमसी निर्मला शिशु भवन रांची, एमसी न्यू शांति नगर गुमला, एमसी गिरीडीह, एमसी साहेबगंज, एमसी दुमका, एमसी निर्मला शिशु भवन हजारीबाग, एमसी शांति निवास धनबाद, एमसी जमशेदपुर, एमसी ईस्ट जेल रोड रांची, ब्रदर ऑफ चैरिटी कांके रोड जवाहरनगर रांची। बच्चों के सौदे पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को बाल संरक्षण आयोग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि नवजातों की खरीद-बिक्री और गर्भवती महिलाओं का शोषण करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बाल संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह पूरे राज्य में ऐसे एनजीओ की जांच करे। गलत कार्यों में लिप्त संस्थाओं को चिह्नित करे और 15 अगस्त तक रिपोर्ट दें। यह जांच पूरी सूक्ष्मता और पारदर्शिता के साथ करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल शोषण और अनैतिक कार्यों में लिप्त कोई भी संस्था हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा।

मिशनरीज ऑफ चैरिटी से बेची गई बच्ची बरामद

मिशनरीज ऑफ चैरिटी से बच्चा बेचने के मामले में रांची पुलिस ने सिमडेगा से बुधवार को एक और बच्ची को बरामद कर लिया। पुलिस ने बच्ची को चाइल्स वेलफेयर कमिटी (सीडब्ल्यूसी) को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार अविवाहित नाबालिग के मां बनने के बाद मिशनरी ऑफ चैरिटी, ईस्ट जेल रोड की सिस्टर कोनसीलिया और वहां काम करने वाली अनिमा इंदवार ने बहला-फुसला कर उससे बच्ची ले लिया था। फिर इस बच्ची को सिमडेगा की रहने वाली शैलजा तिर्की को दे दिया। चार बच्चों को बेचने के आरोप में जेल में बंद मिशनरीज ऑफ चैरिटी ईस्ट जेल रोड की सिस्टर कोनसिलिया और कर्मचारी अनिमा इंदवार को पुलिस रिमांड पर नहीं ले पाई है। पुलिस की ओर से दोनों को पांच दिनों की रिमांड पर देने का प्रे कोर्ट से किया गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस दोनों से पूछताछ के बाद ही कर पाएगी। हालांकि पुलिस ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी ईस्ट जेल रोड से कई दस्तावेज जब्त किए हैं। जिसपर अनुसंधान चल रहा है। जेल जाने से पूर्व दोनों आरोपियों ने बताया था कि चार बच्चों को ही उन लोगों ने बेचा है, जिसमें तीन को पुलिस ने बरामद कर लिया है। सिस्टर कोनसिलिया ने जेल जाने से पूर्व पुलिस को बताया था कि कांटाटोली में जिस बच्चे को बेचा गया, उसने 50 हजार रु. दिए थे, जबकि सिमडेगा में जिस दंपती के हाथों में सौंपा गया, उनसे पैसे नहीं लिए गए थे। जानकारी दोनों ने ईस्ट जेल रोड स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी की हेड सिस्टर मेरिडियन को भी दे दी थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी से संचालित 'निर्मल हृदय' से बच्चों की बिक्री का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन अब वर्ष 2016 से पहले की फाइल की तलाश में है। दरअसल, निर्मल हृदय की जांच के दौरान जिला प्रशासन को अप्रैल 2016 से लेकर अब तक की ही फाइलें मिली हैं। जिसमें वर्ष 2017 से लेकर अब तक 26 बच्चों के गायब होने ही जानकारी मिली थी। क्योंकि, इन बच्चों को सीडब्ल्यूसी के सामने लाया ही नहीं गया था। निर्मल हृदय को लेकर हर दिन चौकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब जिला प्रशासन जब्त किए गए अप्रैल 2016 से पहले की फाइल इसलिए तलाश रही है कि इसमें और भी नए खुलासे हो सकते हैं।

ट्रक में कार ने मारी टक्कर, युवक की मौत

दुमका, हंसडीहा थाना क्षेत्र के नोनीहाट पूजा लाइन होटल के सामने बुधवार सुबह सड़क हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई। जबकि कार में ही सवार दो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हादसा होटल के पास खड़े एक ट्रक में पीछे से कार की टक्कर होने से हुआ। मृतक की पहचान सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुंदरम के रूप में की गई। जबकि घायलों में सुंदरम के दो भाई शामिल हैं। सभी भागलपुर के कहलगांव से अपने घर जामताड़ा आ रहे थे और रास्ते में यह हादसा हुआ। तीनों भाई अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद घर लौट रहे थे। वहीं, हादसे के बाद मृतक के परिजन भी दुमका पहुंच गए हैं। हादसे के बाद मौके पर काफी भीड़ जुट गई और फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

धनबाद, शहर के मिश्रित भवन के सरकारी क्वार्टर में रहने वाली एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका बीएसएस कॉलेज में कॉमर्स की छात्रा थी। मृतक के पिता अमरजीत सिंह ने बताया कि इंटर एग्जाम में दो नंबर कम आने से वो फेल हो गई थी जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। मृतका के पिता अमरजीत सिंह स्थानीय भाजपा नेता हैं। उन्होंने बताया कि काफी दिनों से उनकी बेटी परेशान थी। वो अकेली और शांत रहती थी। उन्होंने उनसे बात की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और कानूनी कार्रवाई में जुट गई।

कार-बोलेरो की भिड़ंत में बच्चे की मौत, ५ घायल

गोपालगंज, जिले में कार और बोलेरो की टक्कर में एक बच्चे की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां दूल्हे की हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक छपरा के जोकहा गांव से बारात सीवान जा रही थी। एक कार में दूल्हा अपने रिश्तेदारों के साथ सवार था। सिधवलिया के पास सामने से आ रही बोलेरो से दूल्हे की कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके साथ सहवाल बनकर जा रहे बच्चे की मौत हो गई। हादसे में घायल हुए सभी लोग दूल्हे की कार में सवार थे। दूल्हे का हाथ और पैर टूट गया है। मृतक बच्चे का नाम बबन है। वह रामु ठाकुर का बेटा था। घायलों के नाम मुकुल कुमार, गोलू कुमार, सुजीत कुमार और राधे राम हैं। हादसे के बाद गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। हादसे के बाद दुल्हन के परिवार वालों को भी घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही सभी लोग सीवान से गोपालगंज पहुंचे। हादसे की वजह से शादी रोक दी गई।

नीतीश कुमार ने रखी देश के सबसे लंबे डबल डेकर फ्लाईओवर की आधारशिला

छपरा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को छपरा में देश के सबसे लंबे डबल डेकर फ्लाईओवर की आधारशिला रखी। इसकी लंबाई करीब 4 किमी और चौड़ाई 5.5 मीटर होगी। फ्लाईओवर की लागत 411.31 करोड़ रुपए है। इसमें से 240 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और बाकी राशि राज्य सरकार देगी। तीन साल में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। डबल डेकर फ्लाईओवर की खासियत है कि इसके लिए सीमित जगह की जरूरत होगी। विभाग के मुताबिक 42 डिसमिल (करीब 18 हजार 293 वर्ग फीट) जमीन की जरूरत है। इसका कारण है कि रोड चौड़ा है। इस दायरे में 150 मकान और दुकान आएंगे। हालांकि कितने मकान निर्माण में आड़े आएंगे इसका एसेसमेंट किया जा रहा है। यह फ्लाईओवर छपरा शहर के पश्चिमी से पूरब की तरफ- भिखारी ठाकुर चौक - गांधी चौक,- मौना चौक,- सलेमपुर- नगरपालिका- श्री नंदन पथ होते हुए बस स्टैंड स्थित जिला स्कूल के गेट पर समाप्त होगा। बाएं तरफ- नगरपालिका चौक से थाना चौक, गांधी चौक से उतर गड़खा, रेवा रोड तक फ्लाइओवर ब्रिज का निर्माण होगा।

मुख्य बाजार होने की वजह से यहां अक्सर यहां जाम की स्थिति रहती है। सड़क चौड़ा करना संभव नहीं है। फ्लाईओवर से जाम से मुक्ति मिलेगी। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की देखरेख में बनेगा। निर्माण के लिए एजेंसी का चयन हो गया है। नीतीश कुमार ने छपरा कमिश्ननरी को 916 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात दी। उन्होंने छपरा-गोपालगंज के बीच नवनिर्मित स्टेट हाईवे जनता को समर्पित किया। यह छपरा-मशरख- बनकट्टी-गोपालगंज के बीच बना है। यह पथ गोपालगंज जिला के मोहम्मदपुर (नेशनल हाईवे 101) से शुरू होकर एनएच- 19 पर बाजार समिति के पास छपरा को जोड़ेगा। 64.71 किमी लंबे इस पथ के निर्माण पर 505 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

दुर्घटना में ड्राइवर और खलासी जख्मी

लातेहार, चंदवा थाना क्षेत्र में रांची-मेदिनीनगर मार्ग पर तालाब के समीप एनएच-75 पर ट्रक और पिकअप वैन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में पिकअप वैन ड्राइवर व खलासी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मौके पर जुटी भीड़ ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहीं, बीएसएनएल टावर के समीप ऑटो की टक्कर से एक बाइक सवार जख्मी हो गया। पहली घटना में पिकअप वैन कीटनाशक लेकर रांची की ओर जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। पिकअप वैन जख्मी ड्राइवर लल्लू कुमार और खलासी संतू कुमार रिश्ते में चाचा-भतीजा हैं। ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में लल्लू की छाती की हड्डी टूट गई है। वहीं, संतू को भी गंभीर चोटें आई हैं। एक्सीडेंट के बाद घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद लल्लू को रिम्स रेफर कर दिया गया है।

ट्रेन की छत पर यात्रा कर रहे २ गिरफ्तार

जहानाबाद, पटना-गया रेलखंड के जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने बुधवार को विभिन्न सवारी गाड़ी में छापेमारी कर 13 यात्रियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए यात्रियों को अग्रेतर कार्रवाई को ले पटना स्थित रेलवे कोर्ट के समक्ष भेजा गया है। सबइंस्पेक्टर मनीष कुमार ने बताया कि पलामु एक्सप्रेस में कोर्ट स्टेशन के समीप चेन पुच्लग कर भाग रहे एक युवक को पकड़ा गया। इसी प्रकार 63243 अप सवारी गाड़ी में छापेमारी कर महिला बोगी में यात्रा कर रहे दो पुरूष यात्री को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं 63244 सवारी गाड़ी के छत पर बैठकर यात्रा कर रहे दो यात्रियों को दबोचा गया।

पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जवान शहीद

घाटशिला, एमजीएम थाना क्षेत्र के बूढ़ा-बूढ़ी पहाड़ के जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान बुधवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हो गया। दोनों ओर से काफी देर तक गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गया। सुरक्षाकर्मियों की मुठभेड़ नक्सली आकाश के दस्ते से हुई थी। दरअसल, सुरक्षाकर्मियों को सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में कुछ नक्सली जुटे हुए हैं और किसी घटना की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना पर जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जंगल में पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसी दौरान जंगल में मौजूद नक्सलियों की सुरक्षाकर्मियों पर नजर पड़ गई। नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी नक्सलियों पर फायरिंग की। इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के जवान निर्मल घोष शहीद हो गए। वहीं, मौका देख नक्सली भागने में कामयाब रहे। इधर, इस घटना के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट कर शहीद जवान को श्रद्धांजली दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा- नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवान निर्मल घोष की शहादत को सलाम। दुख की इस घड़ी में झारखण्ड की सवा तीन करोड़ जनता शहीद निर्मल घोष के परिजनों के साथ है। झारखंड सरकार उनके परिवार की हर संभव मदद करेगी।

नदी किनारे मिली नवजात बच्ची की लाश

रांची, नामकुम थाना क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी किनारे बुधवार को दो महीने की बच्ची की लाश मिली है। सुबह एक शख्स नदी किनारे गया जिसके बाद उसने बच्ची की लाश देखी। इसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस के मुताबिक, बच्ची के गले में जूते का फीता मिला है। आशंका जताई जा रही है कि इसी से बच्ची की गला दबाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल, पुलिस ने बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह नदी किनारे किसी काम से गया था। इस दौरान उसने देखा कि पुल के नीचे नदी किनारे पत्थरों पर एक बच्ची की लाश पड़ी है। उसने इसकी जानकारी 100 डायल कर पीसीआर वैन को दी। फिर नामकुम पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि बच्ची के गले से जूता का फीता मिला है। आशंका जताई जा रही है कि इसी गला घोंटकर बच्ची की हत्या की गई है। पुलिस ने बताया कि नामकुम सड़क के चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगा है। फुटेज की जांच कर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जाएगी।

नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून के कई कड़े प्रावधान किए खत्म

पटना, बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून को लचीला बना दिया है। बुधवार शाम को हुए कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी कानून के कई कड़े प्रावधान को खत्म कर दिए गए।

शराब पीने या बेचने के मामले में जेल में बंद ऐसे लोग जो 3 साल की सजा पूरी कर चुके हैं वो अब जेल से बाहर आएंगे। इसके साथ ही शराब बरामद होने पर जमीन, घर और गाड़ी जब्त करने का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है। इसके लिए बिहार राज्य मद्य निषेध विधेयक में संशोधन पर कैबिनेट की मुहर लगी है। पहले शराब मिलने पर गाड़ी, घर और जमीन जब्त कर ली जाती थी। इसका काफी विरोध हो रहा था। कैबिनेट की बैठक में 37 एजेंडे पर मुहर लगी है।

सुल्तानगंज सावन मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। इससे सावन में भागलपुर के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर वैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अधिक सुविधा जुट पाएगी। कैबिनेट ने ग्रामीण इलाके में बिजली आपूर्ति के लिए 9 नए ग्रिड बनाने की मंजूर दी है। ये ग्रिड अररिया के पलासी समेत अन्य शहरों में बनेंगे। मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों की मौत होने पर सरकार 4 लाख रुपए मुआवजा देगी।

कॉलेज जा रही छात्रा को स्कार्पियो ने रौंदा

बक्सर, एनएच-120 स्थित पुराना भोजपुर-बिक्रमगंज मुख्य मार्ग पर कोरानसराय थानान्तर्गत मुगांव मोड़ के समीप बुधवार को कम्प्यूटर क्लास करने जा रही 17 वर्षीया छात्रा को स्कॉर्पियो ने कुचल दिया। इंटर में पढ़ने वाली छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया। जहां इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन समेत फरार हो गया। बाद में छात्रा की पहचान मुगांव गांव के नाकेन्द्र च्सह की पुत्री गीमा कुमारी के रूप में की गई। सड़क दुर्घटना में छात्रा की मौत के बाद मुगांव के आक्रोशित लोगों ने डुमरांव-बिक्रमगंज मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। आक्रोशित लोग स्कार्पियो चालक की गिरफ्तारी एवं मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। कोरानसराय थानाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात-चीत कर परिवारिक लाभ योजना के तहत मृतका के परिजनों को तत्काल बीस हजार रुपए मुआवजा देकर मामला शांत कराया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि छात्रा डुमरांव स्थित कौशल विकास केन्द्र में कम्प्यूटर का क्लास करने जा रही थी।

अमित शाह एक दिन के दौरे पर रांची पहुंचे

रांची, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक दिन के रांची दौरे पर आज सुबह दस बजे विशेष विमान से यहां पहुंचे। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हवाई अड्डे से बाहर आते ही भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जय श्रीराम के उद्घोष और ढोल नगाड़ों के साथ अमित शाह का भव्य स्वागत किया। दो हजार से अधिक मोटरसाइकिल सवार भाजपा कार्यकर्ता शाह की अगवानी में उनके आगे चल रहे थे। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ शाह पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। शाह यहां पार्टी मुख्यालय पर भाजपा पदाधिकारियों एवं आदिवासी नेताओं से मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी का जायजा लेंगे। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री एवं कार्यालय प्रभारी दीपक प्रकाश ने बताया कि अमित शाह पार्टी कार्यालय में ही बैठकें करेंगे। रांची में ही रात्रि विश्राम कर वह 12 जुलाई को पटना रवाना हो जायेंगे। शाह वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारी की समीक्षा करेंगे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने यहां 14 में से 12 सीटें जीती थीं जबकि मुख्य विपक्षी झारखंड मुक्ति मोर्चा को महज दो सीटें ही प्राप्त हुई थीं।

नेपाल में बारिश से बढ़ा कोसी में उफान, एक दर्जन गांवों में घुसा पानी

वीरपुर, लगातार तीन दिन से नेपाल प्रभाग के पहाड़ी हिस्सों तथा मैदानी क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण एक बार फिर कोसी का जलस्तर बढ़ गया है। मंगलवार को कोसी नदी के जलस्तर दोपहर 04 बजे एक लाख 41 हजार 305 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया। जलस्तर में बढ़ोतरी मंगलवार की सुबह से ही जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते आठ घंटे से पहाड़ी क्षेत्र में बारिस रुकी हुई है और बराहक्षेत्र में डिस्चार्ज अब घटने लगा है। कोसी बराज के 23 फाटक खोले गएः इस कारण मरौना, निर्मली, सरायगढ़, किसनपुर और सुपौल के एक दर्जन गांव में पानी घुस गया है। लोग ऊंचे स्थानों की तलाश में लगे हैं। मवेशी के चारे का संकट होने लगा है। मंगलवार की सुबह 06 बजे कोसी नदी के कोसी बराज कंट्रोल पर जलस्तर 01 लाख 40 हजार 310 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया। वही इसी समय बराहक्षेत्र में डिस्चार्ज 01 लाख 01 हजार 750 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया है। पूर्वी मुख्य नहर में तीन हजार और पश्चिमी मुख्य नहर में दो हजार क्यूसेक पानी सिंचाई के लिए छोड़ा जा रहा था। दोपहर 12 बजे जलस्तर 01 लाख 39 हजार 365 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया। इन गांवों में घुसा पानीःइससे आठ दिन पूर्व भी कोसी बराज के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई थी और जलस्तर एक लाख 55 हजार क्यूसेक को पार कर गया था। तटबंध के भीतरी भाग में बढ़े जलस्तर से निर्मली, मरौना, बसंतपुर, वीरपुर, सुपौल, किसनपुर अंचल क्षेत्र के दर्जनो गांव यथा एकडारा, सोनबरसा, बेंगाटोल, अरराहा, पिरगंज, मोमिनटोला, ठाढ़ि धत्ता, मुरकुचिया, झकराहि, ढोली, परसाही, सिमराहा, सिसवा, डगमारा, कुनोली, कमलपुर, हरीयाही, घोघररीया, सिसोनी, पंचगछिया, सुकमारपुर, खूखनाहा, परसामाधो, मौजहा, जोबहा, घूरन, बलवा, मुंगरर, बेरीया, सितुहर, समेंत दर्जनों गांव में कोसी का पानी आ गया है। इस बाबत जल संसाधन बाढ़ एवं निस्सरण के मुख्य अभियंता प्रकाश दास मुख्य अभियंता इस बात की जानकारी दी है कि कोसी नदी के पूर्वी तटबंध पर सभी स्पर सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार का दबाव नहीं है। कोसी बराज कंट्रोल रूम के सहायक अभियंता लाला प्रसाद ने बताया कि इस साल का यह डिस्चार्ज सबसे अधिक डिस्चार्ज है। बरसात के दौरान कोसी बराज के जलस्तर का उतार चढ़ाव लगातार जारी रहेगा। पिछले दो तीन दिनों से नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से कोसी बराज का जलस्तर में वृद्धि होना एक स्वाभाविक सी बात है। मूसलाधार बारिश से करेह नदी के जलस्तर में उफान आ गया है। इससे जलस्तर में बढ़ोतरी हुआ है। जलस्तर में बढ़ोतरी होने से सूखी हुई सड़कों पर भी नदी का एक फीट पानी बहने लगा है। ऐसे तो बिथान प्रखंड के सलहा से नरपा तक मुख्य सड़क के अलावे सलहा से चिरोटना, सलहा से लाद कपस्या तथा सलहा बुजुर्ग से सलहा चंदन तक जाने वाली सड़क पर करेह नदी का पानी पिछले तीन दिनों से बह रहा है। मंगलवार को हुई बारिश के बाद सलहा से चिरोटना तक जाने वाली मुख्य सड़क पर भी नदी का पानी बहने लगा है। पिछले दो दिनों नदी के जलस्तर में आंशिक रुप से कमी आई थी।

सूरत। रेडियन्ट इन्ट्रनेशनल स्कूल के 6 से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मतदान की कार्यवाही समक्षाई गई। रेडियन्ट स्कुल के विद्यार्थियों ने मतादान करने के लिए जरुरी सारी परिक्रया जानी, स्कुल के शिक्षकों ने भावी नागरीक बनने वाले विद्यार्थियों को मतदान की जानकारी देते हुए उन्हें मतत की शक्ति का ज्ञान दिया।

दक्षिण गुजरात में भारी बारिश की स्थिति : आठ इंच से ज्यादा बारिश

बारडोली, महुवा, चोर्यासी, नवसारी, जलालपोर में हालत बदतर

सूरत। दक्षिण गुजरात में सूरत, वलसाड सहित के क्षेत्रों में बारिश ने बुधवार को लगातार चौथे दिन में भी भारी बारिश हुई थी। बुधवार को सूरत जिला के महुवा, नवसारी और ज लालपोर पर जैसे भारी तबाही हुई हो कुछ ही घंटों में दस इंच बारिश होने पर यह क्षेत्रों में जलबंबाकार की स्थिति पैदा हो गई थी। नवसारी -जलालपोर तो जैसे आज टापू में तब्दील हो गया। लोगों के घरों-दुकानों और बाजारों में बारिश का पानी आ गया था। कहीं पर घुटने तक तो, कहीं पर केडस में जल भराव होने पर स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के कारण नवसारी -जलालपोर में से ६०० से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थल पर स्थानानांतरण कराया गया। यहां जनजीवन ठप हो गया।

गत दिन बारिश ने सौराष्ट्र के गीर सोमनाथ जिले में भारी तबाही मचायी थी और रात को १२ बजे से सुबह के ६ बजे तक में कोडीनार-सूत्रापाडा में मेघगर्जना ने आतंक मचाया। बारिश सांबेलाघार में होने पर सूत्रापाडा में सिर्फ ६ घंटे में ९ इंच बारिश और कोडीनार में ८ इंच बारिश दर्ज की गई थी। जिसकी वजह से सूत्रापाडा-कोडीनार क्षेत्र जैसे टापू में तब्दील हो गया था। सोमात नदी में बाढ़ आने के साथ सभी जगहों पर ज लबंबाकार की स्थिति पैदा हो गई थी। दूसरी तरफ दक्षिण गुजरात के वलसाड-उमरगाम सहित के क्षेत्रों और अमरेली के राजुला, खांभा, जाफराबाद सहित के क्षेत्रों में लगातार तीसरे दिन भी बारिश जारी रही। अमरेली के यह क्षेत्रों में कुछ ही घंटों में पांच इंच से ज्यादा बारिश दर्ज होने पर स्थानीय दली, धातर, कासरिया, मालण सहित की नदियों में बाढ़ आ गया था। इसके साथ अधिकतर क्षेत्रों में जगह-जगह जल भराव हो गया था। सूत्रापाडा में भारी बारिश के कारण सरस्वती नदी में बाढ़ आने पर प्राची तीर्थ ऐसा माधवरायजी मंदिर पानी में डूब गया। इस दौरान बुधवार को बारिश ने दक्षिण गुजरात में महुवा, नवसारी और जलालपोर पर जैसे भारी तबाही आ गई थी। नवसारी -जलालपोर में दस-दस इंच बारिश होने पर सभी जगहों पर ज लबंबाकार की स्थिति पैदा हो गई थी। कई क्षेत्रों में सभी नदी-नाला भर गये थे। जगह-जगह घुटने तक और केडस में जल भराव हो गया था। लोगों के घरों में दुकानों और बाजारों में-कॉम्प्लेक्स में बारिश का पानी आ गया था, जिसे लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नवसारी -जलालपोर के कई रास्ते बंद होने पर कई क्षेत्र संपर्क बिना हो गये। चीखली दक्षिण "तहसील के १० गांवों को जोड़ते रास्ते बारिश का पानी फिर से आने के कारण ठप हो गया था। नवसारी में विजलपोर, धरमपुर, कालियावाडी सहित के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिली थी। ८० से ज्यादा सोसाइटी पानी में डूब गई थी पूर्णा नदी में बाढ़ आने पर प्रशासन को अलर्ट किया गया और नदी किनारे के क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थल पर भेजा गया। इस दौरान हालोल, वालोड और वलसाड क्षेत्र में भी पांच इंच से ज्यादा बारिश दर्ज होने पर अधिकतर क्षेत्रों में जल भराव हो गया।

कनुभाई कलसरीया कांग्रेस में शामिल हुए राहुल गांधी से मिलने के बाद निर्णय

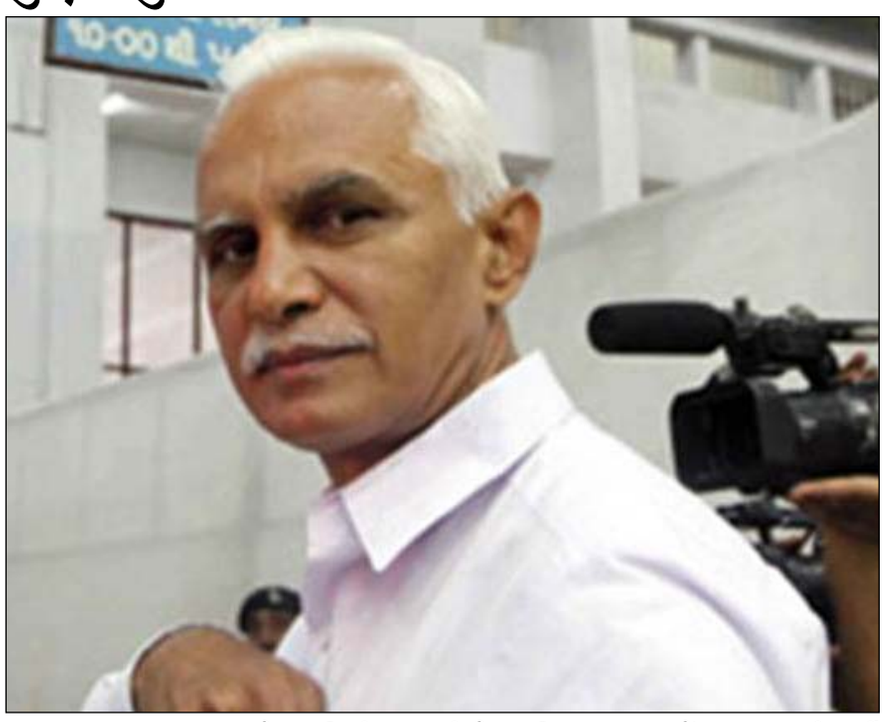

अहमदाबाद। २०१९ के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी गुजरात में और अधिक ताकत एकत्रित करने के प्रयास में लग गई है। भावनगर के शक्तिशाली नेता डॉ.कनुभाई कलसरीया को कोई भी कींमत पर अपनी और खिंचने के प्रयास कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरु किये थे। मिली जानकारी के मुताबिक किसानों के नेता गिनेजाने वाले कनुभाई को मनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से कवायद और अधिक तेज कर दी गई थी। कनुभाई कलसरीया राहुल गांधी से मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गये है। बीजेपी के पूर्व विधायक और २०१४ में आम आदमी पार्टी में शामिल होकर चर्चा जगाने वाले कनुभाई २०१४ में ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले थे किन्तु अंतिम समय में उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया था। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर कनुभाई का संपर्क मे जुट गई थी।

पार्क की गई कार का शीशा तोड़कर ३.६२ लाख की चोरी

अहमदाबाद। शहर के एसजी हाईवे पर स्थित राज पथ क्लब के सामने पार्क की गई कार का शीशा तोड़कर चोरों ने ३.६२ रुपये से भरा थैला लेकर फरार होने पर पूरे क्षेत्र में भारी सनसनी मच गई है। कार सर्विस का गैरेज वाले सचीनभाई एक्सिस बैंक में आरटीजीएस करने के लिए गए तब चोरों ने सिर्फ पांच ही मिनट में कार का शीशा तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था।

इस घटना के मामले में सेटेलाइट रोड पर स्थित आशावरी टावर में रहते और कार सर्विस का गैरेज वाले सचीनभाई शाह ने वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत की है।

शिकायत के अनुसार, गत दिन राजपथ क्लब के सामने रोड पर सचीनभाई अपनी कार पार्क करके एक्सिस बैंक में आरटीजीएस करने के लिए गये थे। पांच मिनट में सचीनभाई अपना काम पूरा करके निकल गये थे। सचीनभाई कार लेकर कुछ दूरी पर पहुंचे तब उनकी कार में आवाज आ रहे होने से वह साइड में खड़े रहे। सचीनभाई ने कार के पीछे देखा तो शीशा टूटा हुआ था और कार में रहा ३.६२ लाख रुपये गायब था। जिसे लेकर वह चिंतित हो गये थे। हालांकि, तुरंत उन्होंने पूरी घटना के मामले में वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज कराकर पुलिस को इस मामले में पूरी जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले में जरूरी अपराध दर्ज करके जांच शुरू की है। वस्त्रापुर क्षेत्र में कार का शीशा तोड़कर चोरी करती गैंग सक्रिय हो गई है। सोमवार को भी वस्त्रापुर के सिंधु भवन रोड पर स्थित आईसीआईसीआई बैंक के सामने पार्क की गई कार का शीशा तोड़कर ५५ हजार रुपये से भरा बैग लेकर चोर फरार हो गये थे, जिसमें पुलिस

सूरत। रथ यात्रा में प्रसाद के लिए बुंदी बनाते भक्त इसकान मंदिर जहांगीरपुरा।

रेलवे की टिकट पर खाने-पीने का मेनु-कीमत भी छापा जाएगा

अहमदाबाद। रेलवे में यात्रा करते यात्रियों को अब खाने-पीने की वस्तुओं पर निश्चित की गई कीमत से अतिरिक्त रुपये नहीं चुकाना पड़ेगा। इंडियन रेलवे केटरींग एंड टूरिजम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अब ट्रेन की ऑनलाइन टिकट या मेन्युअल टिकट पर ही खाने-पीने का मेनु छापा जाएगा जिसमें खाने-पीने की चीजवस्तुओं की कीमत भी छापी गई होगी। रेलवे प्रशासन के इस निर्णय की वजह से यात्रियों को लाभ मिलेगा। रेलवे की टिकट पर हरएक मेनु के साथ हरएक वस्तु की कीमत लिखी हुई होगी जिसकी वजह से यात्रियों को यात्रा के दौरान खाने-पीने के मामले में ठगाई से बच सकेंगे। १५ जुलाई बाद तुरंत ही ऑनलाइन पर आईआरसीटीसी मेनु और कीमत दोनों यात्रियों को उपलब्ध करायी जायेगी। रेलवे स्टेशन पर आईआरसीटीसी के केटरींग वेन्डर खाने-पीने की वस्तुओं को निश्चित की गई कीमत के अलावा अतिरिक्त कीमत वसूल रहे होने की शिकायत प्रशासन को मिली थी इसी वजह से प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। रेलवे की टिकट के साथ यात्रियों को खाने-पीने का लिस्ट भी टिकट में बताया गया होगा। जिसमें चाय-पानी इकोनोमी बिल, लंच-डीनर, वेज या नोनवेज की कीमत के साथ जानकारी छापी गई होगी इसी वजह से संबंधित वेन्डर टिकट पर जो वस्तु और कीमत लिखा होगा इसके ज्यादा से कीमत नहीं वसूल कर सकते है। पहले यात्रियों के पास से ज्यादा कीमत वसूल रहे होने की शिकायतों की वजह से प्रशासन ने ट्वीटर के द्वारा केटरींग की कीमत जारी करने का प्रयास किया था लेकिन बहुत कम यात्रियों ने ट्वीटर का उपयोग किए जाने का मालूम होने पर स्थानी निराकरण के तहत ऑनलाइन टिकट के पीछे खाने-पीने की वस्तुओं की कीमत लिखने का निर्णय किया गया है। जिसका इस अनुसार जानकारी प्रदर्शित की गई होगी।

महादेव मीडिया
रोहताश यादव 9924144499, 7015339195
वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)
हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाईन करवाने के लिए संपर्क करें।
304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com